



तप के माध्यम से मान-प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं रखना चाहिए।

One should not desire fame-respect from austerity.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 271 ● वर्ष : 11 ● रायपुर, बुधवार 24 अप्रैल 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन



विकसित भारत का संकल्प ले रहा आकार इसलिए चुनेंगे मोदी सरकार

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़



एक सांसद ही नहीं चुनना है, देश का उच्चतम भविष्य चुनना है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने ग्राम श्यामतराइ में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को किया संबोधित ● महासमुंद्र, कांक्र और रायपुर लोकसभा की जनता से विकास किया जायेगा

तीसरी बार सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का तेजी से विकास किया जायेगा

धर्मतरी (आरएनएस)। आज मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धर्मतरी जिले के ग्राम श्यामतराइ में विजय संकल्प शंखनाद महारैली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सासद मोहन मंडली, कैबिनेट मंत्री एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री एवं कुरुद विधायक अजय चद्दाकर, महासमुंद्र लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी, कांक्र लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भोजराज नाग, पूर्व मंत्री द्वय चंद्रशेखर साह, प्रेमप्रकाश पांडेय, पूर्व विधायक शिवकार शर्मा, पूर्व विधायक गण रंजना साह, पंक्ती शाह, ब्रवा माकाम, इंद्र चोपडा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा, जिला अध्यक्ष प्रकाश बैंस, भाजपुरी पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पार्वद विजय मोटवानी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पीपी मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे बस्तर में योजना हुआ, देश के अन्य राज्य में मतदान हुआ और उस पहले चरण ने स्पष्ट कर दिया तेसरा का मन साफ़ है, शक्तिशाली, मजबूत सरकार बनानी है। जनता-जनार्दन का भरोसा सिफ़र भाजपा पर है।

इंद्री गठबंधन पर निशाना साथते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके अपने संसदीय पर धर्मतरी को रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का तेजी से विकास किया जायेगा। मोदी ने कहा कि आगे कहा कि छत्तीसगढ़ वह प्रदेश है, जहाँ कोयले की शक्ति, बन संपदा, स्टील की ताकत, विकसित भारत को जीत गति देने की ताकत है। 10 साल में मेरा काम देखा है, सेवा का मुझे मौका दिया है, कोई छुट्टी लिए बिना दिन-रात सेवा का रहा है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपाके लिए जीता रहा हूं, जूँझता रहा हूं क्या कुछ नहीं हुआ 10 साल में। महासमुंद्र सहित अन्य जगह पर पांच नए मैट्डकल कॉन्वेंज स्वीकृत किए। घर-घर तक बिजली, पानी और सस्ती गैस कनेक्शन दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 3 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 4 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।



पंजालूट को पूरा किया। टेंडपता संग्रहकों से की गई है गरंटी को भाजपा सरकार पूरा करेगी। महतारी बंदन योजना लागू होने से आज बहानों के अकार्ड बैंक में सीधे पैसे जा रहे हैं। 18 लाख गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। एसटी, एसपीसी और ओबीसी को सम्मान देकर जब भाजपा देश में आदिवासी राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, ओबीसी उप मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री कानाया तो कांपेस को लोकतंत्र और सम्बन्ध पर खतरा नहीं आने लागता है। 2024 के चुनाव में आपके सेवक नरेन्द्र मोदी को आकांक्षा नामी और जीवनभर नहीं भूलेंगा। छत्तीसगढ़ वालों की जीवनभर लागत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंत में कहा कि मैं 24X7, 2047 के लिए खप जाऊंगा। एक सांसद ही नहीं जाना है, देश का उच्चतम भविष्य चुनाव है। राष्ट्र निर्णायक का यह मौका नाम गवाएं। पहले मतदान पिर जलपान, वीजेपी को दिया आपका एक बोट देश को विकसित बनायेगा। 26 अप्रैल को महासमुंद्र लोकसभा से रूपकुमारी चौधरी, कांक्र लोकसभा से भोजराज नाग और रायपुर लोकसभा से हमारे पुराने मित्र बृजमोहन अग्रवाल को भारी मौतों से विजयी बनाना है। सभी अपना बूथ जीतेंगे और भारी मतदान करवाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 3 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 4 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 5 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 6 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 7 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 8 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 9 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 10 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 11 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में भेजा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो हकदार है उनके खाते में सीधे सीधे पहुंचाएं। 12 लाख करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएं। जब तक देश में भाजपा की सरकार है आपके हक का पैसा आपके पास पहुंचता रहेगा कोई बिचारा की नहीं। 2024 के चुनाव में आपके हक का पैसा आपके खाते में

संपादकीय सियासत में सर्वेक्षणों पर कितना भरोसा

न्यायपालिका गरिमा को अक्षुण्ण रखने का आह्वान

अब की बार पूर्व न्यायाधीशों ने 'न्यायपालिका को अनावश्यक दबाव से बचाने के लिए' देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के चार और हाई कोर्ट के 17 पूर्व न्यायाधीशों ने किसी का नामोल्हेख किए बिना आरोप लगाया है कि कुछ लोग यानी वकील 'अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों एवं व्यक्तिगत लाभों से प्रेरित होकर न्यायिक संस्था को कमज़ोर करने में लगे हैं'। जस्टिस चंद्रचूड़ से ऐसे तत्वों के झांसे में न आकर न्यायिक गरिमा को अक्षण्णु रखने का आह्वान किया गया है। इसी तरह की भाषा-शैली में आज से तीन हफ्ते पहले सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के 600 अधिवक्ताओं, जिनमें हरीश साल्वे जैसे दिग्गज शामिल थे, ने जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। इसमें भी न्यायपालिका के सामने आ रही वैसी ही कठिनाइयों का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी जड़ कांग्रेस की 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाने की मानसिकता' में बताया था तो उजागर हुआ था कि पत्र का ताल्कुक कांग्रेसी विचारधारा के अधिवक्ताओं से है, जो पीठ या न्यायाधीशों पर मनमाफिक फैसले के लिए 'अनुचित दबाव और प्रभाव' डालते हैं। पत्र पर दस्तखत करने वाले जस्टिस ढींगरा ने एक इंटरव्यू में कपिल सिंघल का नाम लेते हुए कहा है कि वे मामले में 'पैरौंकों के दौरान केस की मेरिट पर दलीलें न देकर कहने लगते हैं कि अगर इसे छोड़ नहीं गया तो बवाल हो जाएगा' आदि। इसी समूह में प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी के भी नाम हैं। और भी नाम हो सकते हैं। ये लोग पहले इजलास के अंदर और इसके बाहर इंटरव्यू एवं लेखों के जरिए उन फैसले को सरकार के दबाव में दिया बता कर उनकी अतार्किक आलोचनाएं करते हैं, जो उनके विरोध में आए होते हैं। इससे न्यायपालिका पर खामखाह दबाव बनता है। एक बार जस्टिस चेलमेर ने भी 'इन करोड़ी समूह के अधिवक्ताओं से दिक्कत' बताई थी। न्यायिक क्षेत्र-निचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक-में हाल के दशकों में यह एक फेनोमिना के रूप में विकसित हुआ है। इसमें मनचाही खंडपीठ के लिए तो पीठ बदलने के लिए जोर-जबर्दस्ती की जाती है। इस समस्या का समूचा हिस्सा न्यायालयी ही नहीं है।

संजय कुमार

अब की बार पूर्व न्यायाधीशों ने 'न्यायपालिका' को अनावश्यक दबाव से बचाने के लिए' देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के चार और हाई कोर्ट के 17 पूर्व न्यायाधीशों ने किसी का नामोल्लेख किए बिना आरोप लगाया है कि कुछ लोग यानी बकील 'अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों एवं व्यक्तिगत लाभों से प्रेरित होकर न्यायिक संस्था को कमज़ोर करने में लगे हैं'। जस्टिस चंद्रचूड़ से ऐसे तत्वों के झांसे में न आकर न्यायिक गरिमा को अक्षण्ण रखने का आह्वान किया गया है। इसी तरह की भाषा-शैली में आज से तीन हफ्ते पहले सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के 600 अधिवक्ताओं, जिनमें हरीश सालवे जैसे दिग्गज शामिल थे, ने जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। इसमें भी न्यायपालिका के सामने आ रही वैसी ही कठिनाइयों का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी जड़ कांग्रेस की 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाने की मानसिकता' में बताया था तो उजागर हुआ था कि पत्र का ताल्लुक कांग्रेसी विचारधारा के अधिवक्ताओं से है, जो पीठ या न्यायाधीशों पर मनमाफिक फैसले के लिए 'अनुचित दबाव और प्रभाव' डालते हैं। पत्र पर दस्तखत करने वाले जस्टिस ढींगरा ने एक इंटरव्यू में कपिल सिंबल का नाम लेते हुए कहा है कि वे मामले में 'पैरवी के दौरान केस की मेरिट पर दलीलें न देकर कहने लगते हैं कि अगर इसे छोड़ा नहीं गया तो बवाल हो जाएगा' आदि। इसी समूह में प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंधवी के भी नाम हैं। और भी नाम हो सकते हैं। ये लोग पहले इजलास के अंदर और इसके बाहर इंटरव्यू एवं लेखों के जरिए उन फैसले को सरकार के दबाव में दिया बता कर उनकी अतार्किक आलोचनाएं करते हैं, जो उनके विरोध में आए होते हैं। इससे न्यायपालिका पर खामखावाह दबाव बनता है। एक बार जस्टिस चेलमेर ने भी 'इन करोड़ी समूह के अधिवक्ताओं से दिक्त' बताई थी। न्यायिक क्षेत्र-निचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक-में हाल के दशकों में यह एक फेनेमिना के रूप में विकसित हुआ है। इसमें मनचाही खंडपीठ के लिए तो पीठ बदलने के लिए जोर-जबर्दस्ती की जाती है। इस समस्या का समूचा हिस्सा न्यायालयी ही नहीं है।

A political cartoon by Matt Wuerker. It depicts a massive crowd of people from behind, all with their right hands raised, looking upwards. A single, much larger hand, also with its index finger pointing upwards, rises from the center of the crowd. The background is a warm orange color with radial lines emanating from behind the giant hand, suggesting a sun or a divine source of light.

लोग चलाते थे, जो विधिवत इसका प्रशिक्षण लेकर आते थे। लोग मानते थे कि जब तक मैं सही ढंग से चलाना सीख न लूँ, गाड़ी लेकर सड़क पर नहीं उत सकता। जब टैक्सी की मांग बढ़ी, चालकों की मांग बढ़ी, तब ऐसे लोग भी वाहन चलाने उत्तर आए, जैसीक से प्रशिक्षित नहीं हैं। जब दुनिया में अप्रशिक्षित लोग बड़ी संख्या में आ जाते हैं, तब सर्वेक्षण हो यह सड़क, दुर्घटना की गुंजाइश बढ़ जाती है। इधर कुछ सर्वे में तो जोड़-घाटव के स्तर पर भी त्रुटि देखी गई है, स्थिति हास्यास्पद बनी है और सबसे बड़ी बात यह इससे सर्वेक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित हुर्द है। जब आप सर्वेक्षण की तकनीक से वाकिफ ही नहीं हैं, तो ऐसी गलतियों को आप रोक नहीं सकते। हाँ, सर्वे को 'मैनेज' किया जा सकता है। मतलब, आंकड़ों गतिरोधी उलट-फेर किया जा सकता है। अपने देश में अक्सर हम चर्चा करते रहे हैं कि कॉलेज न भी जाएं, तब भी मनचाही डिग्री मिल जाती है। आप कॉलेज में हाजिर न भी लगाएं, तो आपकी उपस्थिति को 'मैनेज' किया जा सकता है। आंकड़ों या सर्वेक्षण में भी किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विरोध में हेलफर संभव है इहीं वजहों से लोगों की सर्वेक्षण पर आस्था कम हुई।

है। यह सच है कि लोग सर्वेक्षणों को देखना-पढ़ना चाहते हैं, पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं होता है। हम अभी भूले नहीं हैं कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले हुए सर्वेक्षणों का मजाक उड़ाया गया था। चुनाव पूर्व सर्वे ही नहीं, एग्जिट पोल तक गलत निकले थे। ‘शाइनिंग इंडिया’ का खबूब हल्ला था, तय लग रहा था कि भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन वापसी कर लेगा, पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। सर्वेक्षण करने वालों को तगड़ा झटका लगा था। लोग पूछें लगे थे कि सर्वे कैसे किया गया? वैसे, केवल भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी सर्वेक्षण हमेशा सही नहीं होते हैं। हाँ, जिन देशों में दो दलीय व्यवस्था या कम सियासी पार्टियां हैं, वहां सर्वेक्षण अपेक्षाकृत आसान हैं और उनका आकलन भी सटीक निकलता है। अमेरिका की बात करें, तो वहां राष्ट्रपति चुनाव के समय ज्यादातर सर्वे होते हैं, उसमें ज्यादातर दो ही उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है, तो वहां सर्वेक्षण के सटीक होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अपने देश में देखिए, राज्यों में अलग-अलग पार्टियां हैं, उनके बीच गठबंधन होता है और गठबंधन भी स्थिर नहीं रहता है। अपने देश में वर्गीकरण बहुत हैं,

अगर किसो क्षेत्र में एक ही तरह के लोग ज्यादा हों, तो आकलन आसान हो जाता है, पर भारत में आबादी बहुत मिली-जुली है, स्थानीय लोग भी हैं और बाहरी लोगों में भी बहुत विविधता है, तो कोई अनुमान लगाना आसान नहीं है। अपेक्षाकृत कम विविधता वाले अमेरिका में भी सर्वेक्षण पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं, जहां सारे सर्वे सफल रहे हैं। क्या सर्वेक्षणों की गुणवत्ता के लिए प्रयास किए जा सकते हैं? मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि हार-जीत वाले सारे सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, पर पारदर्शिता का प्रदर्शन अनिवार्य होना चाहिए। जब भी कोई आंकड़ा आप साझा करें, तो उसके बार में आपको विस्तार से स्रोत बताने चाहिए, आपने किस नक्सद से सर्वे किया, उसके लिए आपके पास पैसा कहां से आया? सर्वेक्षण के लिए आप किन लोगों के बीच गए? सर्वेक्षण करने वालों को जबाब देने की स्थिति में होना चाहिए, केवल आंकड़े पेश कर देने से काम पूरा नहीं हो जाता। लोगों को सर्वेक्षणों पर जरूर सवाल खड़े करने चाहिए, ताकि सर्वे में अंभीरता आए। सर्वेक्षण के नतीजे गलत हो जा रहे हैं, इसका मतलब कर्तई यह नहीं कि उन पर रोक लगा दी जाए। सर्वे की पारदर्शिता के लिए कानूनी प्रबंध भी किया जा सकता है। प्रेस की आजादी के तहत भी दिशा-निर्देश लाए जा सकते हैं। जैसे आदर्श चुनाव संवित्ता प्रत्याशियों के लिए होती है, उसी तरह से एक संवित्ता चुनावी सर्वेक्षणों के लिए हो सकती है। चुनाव आयोग के पास ताकत है, वह चाहे, तो दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं को बताया जा सकता है कि सही या ईमानदार सर्वेक्षण कैसे किया जाए? कानून भले न बने, पर सर्वेक्षण के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि किसी सर्वेक्षण पर सवाल न उठे और उनके नतीजों से लोगों को सोचने का हनर मिले। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर दंडित होना पड़ता है। वैसे ही विधि का पालन किए बगैर सर्वेक्षण की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

विशेष लेख

आकृष्ण समाज के हर कर्ग में हैं

अवधेश कुमार

इस समय लोक सभा चुनाव को लेकर कई तरह के मत हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे प्रबल मत यह है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपने सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार में लौट रही है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के 370 भाजपा के और सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें मिलने तक की भी भविष्यवाणी करने लगे हैं। दूसरी ओर, विपक्ष इसे खारिज करते हुए कहता है कि भाजपा चुनाव हार रही है और वह 200 सीटों से नीचे चली पाएगी। विपक्ष भाजपा की आलोचना करती है, नरेन्द्र मोदी पर सीधे प्रहार भी करती है, पर अपने समर्थकों और भाजपा विरोधियों के अंदर भी विश्वास नहीं दिला पाती कि वाकई वह भाजपा से सत्ता छीनने की स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन (इंडिया) की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से नेताओं के छोड़कर जाने का कायम सिलसिला इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के अंदर कैसी निराशा और हताशा है। तो फिर इस चुनाव का सच क्या हो सकता है? आगिर 4 जून का परिणाम क्या तस्वीर पेश कर सकता है? इस चुनाव की एक विडंबना और है। भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक वर्ग स्वयं निराशाजनक बातें करता है। व्यक्तिगत स्तर पर मेरी ऐसे अनेक लोगों से बतें होती हैं, जो चुनाव में अपने नेताओं को बताते हैं, कि वे अपने नेताओं को लागू करने के हक में हैं, किंतु पिछड़े इलाकों में लागू करने के पक्ष में नहीं हैं और उनके लिए उन्होंने कहा कि सिंबल सिस्टम ही जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता बुद्धिमान हों। मैं कहना चाहता हूं कि यह संसद ही अगर इस बात की जांच नहीं कर सकती कि मतदाता बुद्धिमान हैं या नहीं, तो और कौन कर सकता है? ... यह कहा गया है कि मतगणना में गड़बड़ी होती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती है। एक प्रत्याशी के पहले सारे मत गिन लिए जाते हैं और उसके बाद पेटी में बंद हो जाते हैं और उसके बाद ही दूसरे प्रत्याशी के मतों की गिनती होती है। मेरी इस बात का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है कि 42 करोड़ बैलेट पेपर और 15 दिन के अंदर हिन्दुस्तान में सुरक्षा के साथ छपवाए जा सकते हैं या नहीं छपवाए जा सकते हैं। ... मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया था। वहां मार्किंग सिस्टम है और वहां पर इस काम में मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, पर वहां भी गलती हुई है।...

में जमान पर हैं या वहां होकर लौट रहे हैं। इनमें ऐसे लगाओं का सच्चा बड़ी है जिनमें उत्साह या आशावाद का भाव न के बराबर मिलता है। वे बताते हैं कि जैसी दली में या बाहर हवा दिखती है धरातल पर वैसी स्थिति नहीं है। जब उनसे प्रश्न करिए कि धरातल की स्थिति क्या है तो सबके उत्तर में कुछ सामान बातें समाहित होती हैं, गलत उम्मीदवार के कारण लोगों के अंदर गुस्सा या निराशा है, गठबंधन को सीट देने के कारण अपने लोगों के अंदर निराशा है, गठबंधन ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनका बचाव करना या जिनके लिए काम करना भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कठिन हो गया है आदि। कुछ लोग अनेक क्षेत्रों में जातीय समीकरण की समस्या का उल्लेख भी करते हैं। एक समूह यह कहता है कि आम कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरकार में उपेक्षा हुई है, उनके काम नहीं हुए हैं, उनको महत्व नहीं मिला है और अब लोगों का धैर्य चूक रहा है। यहां तक कि जिस तरह के लोगों को पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा या टिकट दिया गया है उनसे भी लोग असहमति व्यक्त करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ विपक्ष की बातों को मिला दिया जाए तो निष्कर्ष यही आएगा कि भले भाजपा 400 पार का नारा दे, लेकिन यह हवा हवाई ही है। किंतु क्या यही 2024 लोक सभा चुनाव की वास्तविक स्थिति है? यह बात सही है कि अनेक राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि को शामिल किया जा सकता है वहां पार्टी के अंदर कई जगह उम्मीदवारों को लेकर विरोध है। कुछ उपयुक्त लोगों को टिकट न मिलना तथा ऐसे सांसदों को फिर से उत्तराखण्ड जिनको लेकर कार्यकर्ता नाराजगी प्रकट करते रहे हैं विरोध का एक बड़ा कारण है। साथी दलों ने भी भाजपा के लिए समस्याएं पैदा की हैं। उदाहरण के लिए बिहार में लोजपा ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो परिवारवाद का साक्षात् प्रमाण है और भाजपा के लोगों के लिए इनका बचाव करना कठिन है। कुछ साथी दलों ने प्रभाविता और साक्षमता की जगह व्यक्तिगत संबंध और परिवार को टिकट देने में प्रमुखता दिया। बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रचार के लिए गए और वहां भाजपा के लोगों ने पूरी ताकत लगाई। इसका असर भी हुआ। बावजूद यह प्रश्न किया जा रहा है कि किसी नेता के बहनोंई या 26 साल की एक लड़की को, जिसके पिता साथी दल में नेता हैं उनको हम अपना नेता या प्रतिनिधि मानकर कैसे काम करें? स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीति परिवार के ईर्द-गिर्द सिमटी रही। जद (यू) की ओर से भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं, जिन्हें भाजपा और राजग के परंपरागत कार्यकर्ता और समर्थक स्वीकार नहीं कर रहे। भाजपा के भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम पर उन्हें थोप दिया गया है।

विभूति मिश्र

मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा, पर फेल अगर होता है, तभी तो सुधार की बात कही जाती है ... सुधार की बात सिंबल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए ... गांव में आज दिन भी बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जाकर गरीब आदमी को बोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा-धमकाकर जिसके चाहेगा, बोट दिलवा देगा और उसको कह देगा विफ्फालों बक्से में बोट डालते। उस गरीब आदमी के दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको बोट दे रहा है यह उसके कहने के मुताबिक बोट दे रहा है। ... गोपनीयत नहीं रह पाएगी। आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में मतदाता को शिक्षित किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना मत न बेचे। ... आप यह भी कहते हैं विप्रत्याशी उनको बुद्धिमानी से शिक्षित करें। मैं पूछूँ चाहता हूँ कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जनसेवा में लगाया है? ... जहां तक इल्लाजम लगाने का ताल्कुक है वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आकर बैठ जाए, तो उनके खिलाफ भी इल्लाजम लगाया जाएं। ... हमारे यहां के चुनाव की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे (सुकुमार) सेन साहब चुनाव आयुक्त थे..., उन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया...। यहां कुछ लोगों का दिल्ली, कलकत्ता बंबई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से संवेदन

छूट गया है। ...केरल में जो उप-चुनाव हुआ, उसे कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिए थे, तो केरल का चुनाव कोई उदाहरण नहीं है मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा, पर फेल अगर होता है, तभी तो सुधार की बात कही जाती है। ...सुधार की बात सिंबल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते व्यक्तों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए? ...गांव में आज दिन भी बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जाकर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा-धमकाकर जिसको चाहेगा, वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो। उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उसके कहने के मुताबिक वोट दे रहा है। ...गोपनीयता नहीं रह पाएगी। आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में मतदाता को शिक्षित किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना मत न बेचे। ...आप यह भी कहते हैं कि प्रत्याशी उनको बुद्धिमानी से शिक्षित करें। मैं पूछूंगा चाहता हूं कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जनसेवा में लगाया है?... जहां तक इल्जाम लगाने का ताल्लुक है, वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आकर बैठ जाएं, तो उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए जाएंगे। ...हमारे यहां के चुनाव की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे (सुकुमार) सेन साहब चुनाव आयुक्त थे..., उन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया....। यहां कुछ लोगों का दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से संपर्क छूट गया है। ...केरल में जो उप-चुनाव हुआ, उसे कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिए थे, तो केरल का चुनाव कोई उदाहरण नहीं है मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा।

सीखते, तो अभी तक सब सज्जन हो जाते

विभूति मिश्र

मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा, पर फेल अगर होता है, तभी तो सुधार की बात कही जाती है। ...सुधार की बात सिंबल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए? ...गांव में आज दिन भी बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जाकर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा-धमकाकर जिसको चाहेगा, वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो। उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उसके कहने के मुताबिक वोट दे रहा है। ...गोपनीयता नहीं रह पाएगी। आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में मतदाता को शिक्षित किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना मत न बेचे। ...आप यह भी कहते हैं कि प्रत्याशी उनको बुद्धिमानी से शिक्षित करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जनसेवा में लगाया है?... जहां तक इल्जाम लगाने का ताल्कूह है, वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आकर बैठ जाए, तो उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए जाएं। ...हमारे यहां के चुनाव की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे (सुकुमार) सेन साहब चुनाव आयुक्त थे..., उन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया...। यहां कुछ लोगों का दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से संपर्क छूट गया है। ...केरल में जो उप-चुनाव हुआ, उसे कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिए थे, तो केरल का चुनाव कोई उदाहरण नहीं है मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा, पर फेल अगर होता है, तभी तो सुधार की बात कही जाती है। ...सुधार की बात सिंबल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए? ...गांव में आज दिन भी बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जाकर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा-धमकाकर जिसको चाहेगा, वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो। उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उसके कहने के मुताबिक वोट दे रहा है। ...गोपनीयता नहीं रह पाएगी। आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में मतदाता को शिक्षित किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना मत न बेचे। ...आप यह भी कहते हैं कि प्रत्याशी उनको बुद्धिमानी से शिक्षित करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जनसेवा में लगाया है?... जहां तक इल्जाम लगाने का ताल्कूह है, वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आकर बैठ जाए, तो उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए जाएंगे। ...हमारे यहां के चुनाव की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे (सुकुमार) सेन साहब चुनाव आयुक्त थे..., उन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया...। यहां कुछ लोगों का दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से संपर्क छूट गया है। ...केरल में जो उप-चुनाव हुआ, उसे कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिए थे, तो केरल का चुनाव कोई उदाहरण नहीं है मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा।

लोगों को सिखाएँ कि अपना वोट नहीं बेचें

एक सन

A close-up photograph of a person's hand, palm facing forward, pointing their index finger upwards. A small, dark blue ink mark is visible on the tip of the index finger. The hand is set against a solid red circular background, which is itself centered on a larger, darker grayish-red circular area. The lighting creates strong shadows on the fingers.

देखकर अपनी पसंद की पेटी तलाश कर सकता है तो कोई कारण नहीं कि वह मतपत्र पर भी वह चिन तलाश कर सके, जिस पर वह निशान लगान चाहता है। ...वास्तव में मेरा तो विचार यह है कि ज प्रणाली हम अब अपनाने जा रहे हैं, वह पहले बाल प्रणाली से अधिक समल है।... मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे मतदाता इतने जाहिल हैं। बावास्तव में यह है कि हम उन्हें भली प्रकार समझा नहीं हैं। शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है। ...जिन बुराइयों के निराकरण के लिए यह प्रणाली निकाल गई थी, वे अनेक हैं। सबसे पहली बात तो यह है विगरीब मतदाता मतपत्रों को बाहर ले जाकर बेच देथे। प्रजातंत्र के लिए इससे अधिक खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। वर्तमान प्रणाली में मतदाता मतपत्र का बाहर नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पेटी में डाला जाएगा। ...एक अन्य बात यह है कि बहुत से लोग मतपत्र लेकर उसे कहीं भी रखकर और नमस्कार करके चतुर्पास जाते हैं। ...अब संसदीय सीट की मतगणना को तीलीजिए। बहुत से गणक मेज पर बैठते हैं औं

निकालकर गिने जाते हैं। उस समय उनको एक-दूसरे में आसानी से मिलाया जा सकता है। एक बार उनके मिल जाने पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा मतपत्र किसके लिए था। वर्तमान प्रणाली में यह दोष भी दूर हो जाएगा। निशान लगाकर मतदान की नई प्रणाली को तुरंत क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। हम यह चुनाव आयुक्त पर छोड़ देंगे कि वह जिन क्षेत्रों को ठीक समझें, उनको नई प्रणाली लागू करने से छूट दे सकें। हम स्वयं निर्धारण नहीं करेंगे। ... आयुक्त के लिए नई प्रणाली को तुरंत लागू करना कठिन होगा। हमें याद रखना चाहिए कि आगामी वर्षों में हमारे देश में साक्षरता भी बहुत बढ़ जाएगी। अनुमान है, 1961 की जनगणना में 40 प्रतिशत साक्षरता हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली को यथासीध लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए। निशान लगाकर मतदान के विरुद्ध केवल एक तर्क पेश किया गया है और वह यह कि जब संसद के माननीय सदस्य भी बटन ठीक से नहीं दबा सकते, तो अशिक्षित मतदाता मतपत्र पर सही निशान कैसे लगा सकते हैं? ... हमें स्वीकार करना

